साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 8, अंक : 23 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 25 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लालकिले पर मिशन लाइफ के विषय पर मंडप बनायेगा

नई दिल्ली। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 26 से 31 जनवरी के बीच भारत पर्व के दौरान दिल्ली में लालकिले पर मिशन लाइफ के विषय पर एक मंडप बनायेगा। यह मंडप 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह के अवसर पर स्थापित किया जाएगा, जिससे जनता को शिक्षित और संवेदनशील बनाया जा सके ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहायता और निरंतर जीवन को बढ़ावा दिया जा सके।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अक्तूबर 2022 में मिशन लाइफ की शुरुआत की थी जिसका संदेश है- मिशन लाइफ जलवायु के खिलाफ लड़ाई कर सके जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे सके। यह मंडप सामान्यजनों के लिए 26 जनवरी से 31 जनवरी 2023 के बीच सायं पांच बजे से रात नौ बजे तक खुला रहेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि एक मिशन लाइफ का संदेश एलईडी स्क्रीन, मोशन सेंसर वॉल, इंटरएक्टिव वॉल और लाइव एआर वॉल जैसे मीडिया मंचों के माध्यम से दिखाया जाएगा।

साइकिल यात्रा- पर्यावरण संरक्षण को लेकर एवरेस्ट की चढ़ाई का लक्ष्य

बारां.देश में प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण जागरूकता को लेकर 22 वर्षीय पप्पू चौधरी साइकिल से शहर सहित गांव-गांव पहुंच रहे हैं. वह गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर युवाओं को पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए जागरूक कर रहे हैं. पप्पू चौधरी को घर से निकले 141 दिन हो गए है. उन्होंने यह मुहिम 1 सितंबर 2022 को शुरू की थी. जहां वे अब तक 23 हजार 780 किलोमीटर यात्रा साइकिल से कर चुके है. शुक्रवार को पप्पू बारां जिले के अंता पहुंचे.

नागौर के खींवसर निवासी पप्पू चौधरी ने बताया कि वह माउंट एवरेस्ट की यात्रा के लिए साइकिल से घर से निकले है. जहां राजस्थान के सभी 33 जिले की यात्रा करते हुए भारत के सभी राज्यों की यात्रा करते हुए एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल यात्रा करते हुए पहुंचेंगे. पप्पू चौधरी का लक्ष्य 2025 तक एवरेस्ट की चढ़ाई करेंगे. उनकी साइकिल यात्रा करने के पीछे का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है. पप्पू ने बताया कि अब तक मैं जहां से होकर निकला हूं, वहां वहां हमने पौधारोपण किया है. वहीं युवाओं को पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने का संदेश दिया. साथ ही पौधे को पेड़ बनने तक उनकी सुरक्षा करना का संदेश दिया.

प्रदूषण से जूझ रहा देश.. साइकिल यात्रा पर निकले पप्पू ने कहा कि आज देश के सभी राज्य पर्यावरण प्रदूषण से जूझ रहे हैं. वायु प्रदूषण के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है. जिसके कारण पर्यावरण के प्रति लापरवाही बढ़ती जा रही है. पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर जंगलों की तबाही की जा रही है. जिससे इंसान को सांस लेने में भी तकलीफ पैदा हो रही है इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आम लोगों को पौधा लगाकर पेड़ बनने तक उसकी सुरक्षा के प्रति जागरूक करना मेरा लक्ष्य है.

पर्यावरण संरक्षण के लिए लाइफस्टाइल में करना होगा बदलाव

नई दिल्ली। एसजीटी विश्वविद्यालय के नौवें दीक्षांत समारोह में छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन और श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि दुनिया आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है लेकिन इस बीच जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां भी पूरी दुनिया के समक्ष हैं। ऐसी स्थिति में हम सबका दायित्व है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को बदलें और हमारा लाइफस्टाइल पर्यावरण-संरक्षण के अनुकूल हो।

यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा इको-फ्रेंडली लाइफ का मंत्र देते हैं। हम सभी को इसे अपनाना चाहिए। दीक्षांत समारोह में जिन छात्र-छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गईं, उन्हें शुभकामनाएँ देते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सीखने की प्रवृत्ति, लगातार कार्य करते रहने की भावना, नेतृत्व के लिए तैयारी करना और सामाजिक दायित्व की भावना का होना जरूरी है। दीक्षांत समारोह की विधिवत शुरुआत एसजीटी विश्वविद्यालय के चांसलर पद्मश्री रामबहादुर राय ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि श्री अरुण जेटली फाउंडेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर संगीता जेटली, दशमेश एजुकेशनल चेरिटेबल ट्रस्ट की चेयरपर्सन मधुप्रीत कौर चावला, मैनेजिंग ट्रस्टी मनमोहन सिंह चावला, वाइस चांसलर डॉ. ओपी कालरा, रजिस्ट्रार डॉ. जोगिंदर यादव, एसजीटी यूनिवर्सिटी गवर्निंग बॉडी के सदस्य राजकुमार भाटिया सहित विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, अध्यापक तथा छात्र-छात्राएं मौजूद थे। दीक्षांत समारोह के प्रथम चरण में फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज के एमबीबीएस, एमडी तथा एमएस के छात्र-छात्राओं को डिग्रियाँ प्रदान की गईं। इसके साथ ही विभिन्न विषयों में पीएचडी करने वाले छात्र-छात्राओं को भी डिग्रियां दी गईं। इस अवसर पर प्रख्यात पत्रकार तथा प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य अशोक कुमार टंडन को डी.लिट्. की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। समारोह के दूसरे चरण में एसजीटी डेंटल कॉलेज, हास्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, आयुर्वेद, फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, फैकल्टी ऑफ फिजियोथेरेपी और फैकल्टी ऑफ लॉ के छात्र-छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गईं। समारोह के दूसरे चरण के मुख्य अतिथिदिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वाइस चांसलर प्रो. रमेश के. गोयल थे।

महाराष्ट्र में खोजा गया नया पठार, प्रजातियों के अस्तित्व पर अध्ययन के लिए अहम

मुंबई। महाराष्ट्र में खोजा गया नया पठार, प्रजातियों के अस्तित्व पर अध्ययन के लिए अहमविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पीआईबी पर प्रकाशित किया गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पीआईबी पर प्रकाशित किया गया

भारत में दुनिया भर की चार जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक पश्चिमी घाट का इलाका है। शोधकर्ताओं द्वारा महाराष्ट्र राज्य के ठाणे इलाके में खोजे गए 24 अलग-अलग प्रजातियों के पौधों और झाड़ियों की 76 प्रजातियों वाला एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार खोज निकाला गया है। यह खोज डॉ. मंदार दातार के नेतृत्व में पुणे के अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट (एआरआई) की टीम ने हाल ही में ठाणे जिले के मंजरे गांव में की है। यह इस क्षेत्र में पहचाना जाने वाला चौथे प्रकार का पठार है। पिछले पहचाने गए तीन उच्च और निम्न ऊंचाई पर लेटराइट और अधिक ऊंचाई पर बेसाल्ट के पठार हैं। शोधकर्ताओं ने कहा यह पठार विविध प्रजातियों की जानकारी का भंडार साबित हो सकता है। यह प्रजातियों के अस्तित्व पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने और रॉक वैश्विक संदर्भ में आउटक्रॉप्स की संरक्षण आवश्यकताओं और उनके विशाल जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण हो सकता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि पुणे में अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट (एआरआई) एक दशक से इसकी जैव विविधता विशेष रूप से इसके रॉक आउटक्रॉप्स का अध्ययन कर रहा है। पठार पश्चिमी घाट में एक प्रमुख भूदृश्य हैं, जो स्थानीय प्रजातियों की वर्चस्व के कारण महत्वपूर्ण हैं। उन्हें एक प्रकार के रॉक आउटक्रॉप के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रजातियों को अनुकूल करने के लिए अनोखे और चुनौतीपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। इन आउटक्रॉप में मौसमी पानी की उपलब्धता, सीमित मिट्टी और पोषक तत्व होते हैं, जो उन्हें प्रजातियों के अस्तित्व पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए आदर्श प्रयोगशाला बनाते हैं। पठार इस प्रकार की जानकारी का एक बहुमूल्य स्रोत है जहां प्रजातियां चरम स्थितियों में जीवित रह सकती हैं। टीम ने पठार का सर्वेक्षण करते हुए 24 विभिन्न प्रजातियों के पौधों और झाड़ियों की 76 प्रजातियों को दर्ज किया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक महत्वपूर्ण खोज है क्योंकि पठार तीन अन्य रॉक आउटक्रॉप्स के साथ वनस्पति साझा करने के साथ-साथ कुछ अनोखी प्रजातियों को भी समेटे हुए है। यह अलग-अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों में प्रजातियों के परस्पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक अनूठी मॉडल प्रणाली प्रदान करता है।

शोध में उत्तरी पश्चिमी घाट में ठाणे जिले के मंजरे गांव में नए खोजे गए निम्न स्तरीय बेसाल्ट पठार के महत्व पर प्रकाश डाला है, जो समुद्र तल से औसतन 156 मीटर ऊपर है।

जलवायु परिवर्तन से पंजाब में फसलों को होगा भारी नुकसान, 24 फीसदी तक घट सकता है मक्का उत्पादन

पंजाब। जलवायु में जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं उसका खामियाजा आने वाले कुछ वर्षों में पंजाब में रबी और खरीफ फसलों को भुगतना पड़ सकता है। इस बारे में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, लुधियाना के कृषि अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों द्वारा किए नए अध्ययन से पता चला है कि अगले 27 वर्षों में बदलती जलवायु के साथ पंजाब में मक्के का उत्पादन 13.1 फीसदी तक गिर सकता है।

वहीं जलवायु में आते यह बदलाव यदि भविष्य में भी जारी रहते हैं तो 2080 तक उत्पादकता को होने वाला यह नुकसान बढ़कर 24.4 फीसदी तक जा सकता है। वहीं यदि कपास की बात करें तो जहां 2050 तक उसका उत्पादन 11.4 फीसदी तक गिर सकता है, वहीं 2080 तक इसके उत्पादन में गिरावट का यह आंकड़ा बढ़कर 23.4 फीसदी तक जा सकता है। इस बारे में विस्तृत जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा प्रकाशित जर्नल %मौसम% के नवीनतम अंक में सामने आई है। अपने इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पिछले 35 वर्षों (1986 से 2020) के वर्षा और तापमान के आंकड़ों का इस्तेमाल किया है, जिससे पंजाब की पांच प्रमुख फसलों की पैदावार पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अनुमान लगाया जा सके। शोध के जो नतीजे सामने आए हैं उनके अनुसार अधिकांश फसलों में औसत तापमान में वृद्धि के साथ उसकी उत्पादकता में गिरावट दर्ज की गई है।

क्या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है बेहतर विकल्प- वहीं यदि खाद्यान फसलों की बात करें तो जहां जलवायु में आते बदलावों और बढ़ते तापमान के चलते अगले 27 वर्षों में गेहूं उत्पादन में 5.67 फीसदी की गिरावट आ सकती है जो 2080 तक बढ़कर 6.5 फीसदी तक पहुंच सकती है। इसी तरह वैज्ञानिकों ने पंजाब के धान उत्पादन में भी 1.7 फीसदी की गिरावट का अंदेशा जताया है, जो 2080 तक बढ़कर 2.7 फीसदी तक जा सकता है। शोध के मुताबिक बदलती जलवायु के साथ आलू उत्पादन में भी गिरावट आ सकती है, जिसके 2050 तक 4.7 फीसदी रहने की आशंका जताई गई है। देखा जाए तो पंजाब में कृषि पर मंडराता यह खतरा न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश में कृषि उत्पादन के लिए खतरा है। यदि पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो पंजाब देश का करीब 12 फीसदी अनाज उत्पादित करता है। यही वजह है कि इसे देश की फ़ूड बास्केट या अन्न भंडार के खिताब से भी नवाजा गया है।

शोध के मुताबिक जहां 1986 से 2020 के बीच जहां कई फसलों के सीजन में न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है, जोकि धान, मक्का और कपास जैसी फसलों के उत्पादन के लिए नुकसान देह है। आंकड़ों के मुताबिक इस जहां धान के सीजन के न्यूनतम तापमान में इस अवधि के दौरान 1.25 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है।

वहीं कपास के सीजन के न्यूनतम तापमान में 1.16 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि आई है। हालांकि आलू और गेहूं की फसलों के लिए बढ़ता न्यूनतम तापमान फायदेमंद हो सकता है। इसी तरह यदि इन 35 वर्षों की अवधि के दौरान बारिश से जुड़े आंकड़ों को देखें तो धान के सीजन (जून से सितम्बर) में वर्षा में 107.34 मिलीमीटर की गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरह मक्के के सीजन (मई से अक्टूबर) में भी इसमें 257.13 मिलीमीटर की कमी रिकॉर्ड की गई है।

देखा जाए तो कृषि उत्पादन पर मंडराता जलवायु परिवर्तन का यह खतरा न केवल फसलों बल्कि किसानों के लिए भी बड़ा खतरा है। जो उनकी आय के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा के लिए भी संकट पैदा कर सकता है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने जलवायु में आते बदलावों और उनसे पैदा हुए खतरों से निपटने के लिए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पर ध्यान देने का सुझाव दिया है।

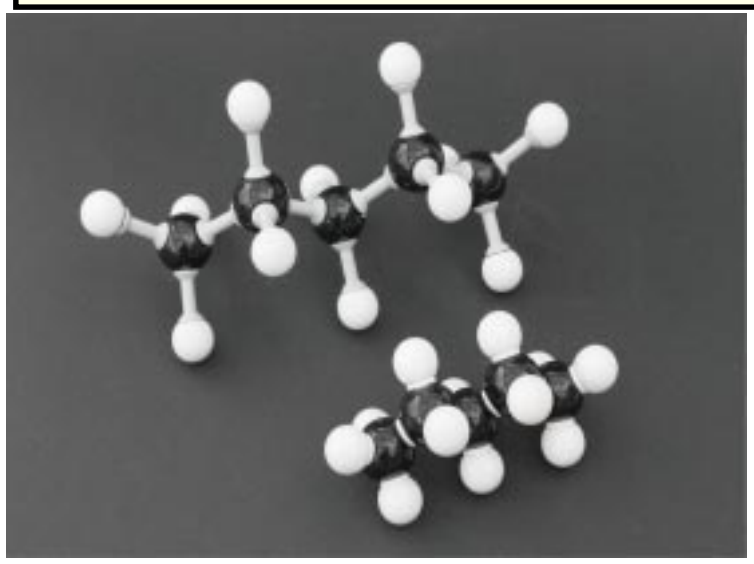

असम के डिब्रूगढ़ में हो सकता है हाइड्रोकार्बन, भारतीय वैज्ञानिकों ने लगाया पता

डिब्रूगढ़ वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया कि कैसे थ्री-डी भूकंप संबंधी आंकड़ों का उपयोग करके एक बेसिन या घाटी में तलछट के इतिहास को समझा जा सकता है। इस प्रक्रिया से हाइड्रोकार्बन की खोज करने में सफलता मिल सकती है और यह इलाके की भूमि या भूकंप की संरचना के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है।

क्या होता है हाइड्रोकार्बन?

हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इनका मुख्य स्रोत जमीन से निकलने वाला तेल है। प्राकृतिक गैस में भी केवल हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। आमतौर पर, हाइड्रोकार्बन रंगहीन गैसें होती हैं जिनमें बहुत कम गंध होती है। हाइड्रोकार्बन में सरल या अपेक्षाकृत जटिल संरचनाएं हो सकती हैं और इन्हें आम तौर पर चार उपश्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे अल्केन्स, अल्केन्स, एल्केनीज और सुगंधित हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का अध्ययन अन्य कार्यात्मक समूहों के रासायनिक गुणों और उनकी जानकारी प्रदान कर सकता है। इसके अलावा, प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे हाइड्रोकार्बन का उपयोग तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के रूप में व्यावसायिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। बेंजीन, सबसे सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन में से एक, यह कई सिंथेटिक दवाओं के संश्लेषण के लिए कच्चे माल के रूप में कार्य करता है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपरी असम बेसिन उत्तर में हिमालय पर्वत का इलाका है, दक्षिण में नागा पहाड़ियों और पूर्व में मिश्मी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अधिकांश तलछट तृतीयक काल यानी 25 लाख साल पहले का समय जो हाल के तलछट के आवरण से संबंधित हैं। बेसिन में इन तलछटों की जानकारी के लिए भूकंपीय आंकड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (डब्ल्यूआईएचजी) के निदेशक डॉ. कलाचंद सेन तथा डॉ प्रियदर्शी चिन्मय कुमार के साथ, डब्ल्यूआईएचजी के वैज्ञानिक ने ऊपरी असम बेसिन के डिब्रूगढ़ क्षेत्र के भीतर उच्च-रिज़ॉल्यूशन थ्री-डी भूकंपीय आंकड़ों से वहां जमा तलछट और वहां के वातावरण की गुथी सुलझाने की प्रक्रियाओं का पता लगाया। यहां बताते चले कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (डब्ल्यूआईएचजी), भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। अध्ययन से पता चलता है कि ओलिगोसीन बरेल कोल-शेल यूनिट जो कि यहां 3.39 से 2.04 करोड़ साल पहले जमा हुआ तथा, इसकी बनावट और विशेषताएं विकृत, लहरदार, अस्तव्यस्त और विषम बनावट से जुड़ी हैं, जो इसके निक्षेपण के दौरान प्रचलित एक गहरी आधारभूत स्थिति की और इशारा करती हैं।

बच्चे ध्यान रखें, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा - राष्ट्रपति

नई दिल्ल राष्ट्रपति शद्रौपदी मुर्मू ने बच्चों को कहा कि वे यह ध्यान रखें कि वे जो कुछ भी करते हैं, उससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है।

राष्ट्रपति शद्रौपदी मुर्मु ने दिल्ली में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 2023 प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चे हमारे देश की अमूल्य संपत्ति हैं। उनके भविष्य-निर्माण के लिए किया गया हर प्रयास हमारे समाज और देश के भविष्य को स्वरुप प्रदान करेगा। हमें उनके सुरक्षित और खुशहाल बचपन तथा उज्?जवल भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। बच्चों को पुरस्कार देकर, हम राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को प्रोत्साहित और सम्मानित कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ पुरस्कार विजेताओं ने इतनी कम उम्र में ही इतना अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया है कि उनके बारे में जानकर न केवल आश्चर्य हुआ बल्कि मैं अभिभूत हो गयी। उनके उदाहरण सभी बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणादायी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हम देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कड़े संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली है। इसलिए नई पीढ़ी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभी इस स्वतंत्रता के मूल्य को पहचानें और इसकी रक्षा करें। उन्होंने बच्चों को सलाह दी कि वे देश के हित के बारे में सोचें और जहां भी मौका मिले देश के लिए काम करें। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय जीवन-मूल्यों में परोपकार को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जीवन उन्हीं के लिए सार्थक है, जो दूसरों के लिए जीते हैं। संपूर्ण मानवता के प्रति प्रेम का भाव, पशु-पक्षियों और पौधों की देखभाल की संस्कृति; भारतीय जीवन-मूल्यों का अंग है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आज के बच्चे पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक हैं। उन्होंने बच्चों को कहा कि वे यह ध्यान रखें कि वे जो कुछ भी करते हैं, उससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। उन्होंने उनसे पौधे लगाने और उनकी रक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने बच्चों से ऊर्जा बचाने और बड़ों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को छह श्रेणियों - कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा और खेल में उनकी उत्कृष्टता के लिए प्रदान किये जाते हैं। इस वर्ष, कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल की श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए।

पर्यावरण सुधार-दिल्ली में फैसला, निगम को पर्यावरण सुधार के लिए मिलेंगे 24 करोड़ रुपए

ग्वालियर 15 वें वित्त आयोग की बैठक सोमवार को नई दिल्ली के इंद्रा पर्यावरण भवन में हुई। बैठक में ग्वालियर नगर निगम के सिटी प्लानर पवन सिंघल और इंजीनियर पवन शर्मा हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। ग्वालियर नगरीय सीमा में पिछले कुछ सालों में पर्यावरण सुधार के लिए किए गए कार्यों को प्रजेंटेशन दिखाया गया। इसके बाद नगर निगम को 24 करोड़ रुपए की राशि देने का फैसला लिया गया है।

देश की 100 स्मार्ट सिटी की बैठक सोमवार को पणजी (गोवा) में हुई। यहां पर पहले 20 सिटी का प्रेंजेंटेशन होना था। लेकिन आखिरी वक्त में 16 सिटी का तय किया गया। ग्वालियर ने अपने प्रजेंटेशन में बताया कि कंट्रोल कमांड सेंटर को आगे चलाने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। इसमें स्मार्ट सिटी जो काम करके दे रही है। उससे इनकम आ सकती है। गौरतलब है कि यहां से हिस्सा लेने के लिए स्मार्ट सिटी के नागेंद्र सक्सेना और वीरेंद्र शाक्य पणजी में गए हुए है। 24 जनवरी को भी बैठक होगी।

सस्ते रेत का रास्ता साफ नहीं-सरकार से 19 खदानों को मंजूरी, पर्यावरण विभाग से परमिशन न मिलने पर 10 माह से रुका है खनन

फाजिल्का नई सरकार के गठन के 10 माह बीत जाने के बावजूद भी लोगों को सस्ती रेत का लाभ नहीं मिल पा रहा हालांकि सरकार द्वारा राज्य के 3 जिलों की रेत की खदानों को क्लीयरेंस दी जा चुकी है किंतु फाजिल्का जिले की 19 खदानों को इनवायरमेंट कंट्रोल की परमिशन न मिलने के कारण लोगों को फिलहाल सस्ती रेत का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिस कारण लोग सरकार को कोसते नजर आ रहे हैं।

लोगों का कहना है कि दूसरी सरकारों की तरह उक्त सरकार भी रेत को लेकर ढीलमूल रवैया अपना रही है, जिसके चलते 10 माह बीत जाने के बावजूद भी रेत माफिया अपनी मनमानियां कर रहा है तथा लोगों को सस्ती रेत के नाम पर फिलहाल लॉलीपाप ही मिल रहे हैं।

गांव बाधा में शुरू हुई रेत खदान कुछ घंटों में हुई बंद

कुछ दिन पूर्व फाजिल्का के बाधा गांव स्थित एक खदान को सरकारी आदेशों के बाद शुरू किया गया था किंतु शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही अनियमताओं की शिकायत के चलते उक्त खदान को फिर से बंद कर दिया गया तथा लोगों को सस्ती रेत मिलने के सपने वहीं के वहीं धरे रह गए।

1350 की मिलने वाली ट्राली 7 से 10 हजार रुपए में बेच रहा माफिया

सरकारी रेट के अनुसार लोगों को 9 रुपए प्रति घन फुट के हिसाब से सरकार द्वारा रेट तय किए गए हैं जिसके हिसाब से आम लोगों को 150 फुट केपेसिटी वाली ट्राली लगभग 1350 के अलावा ट्रांसपोर्ट चार्जेस सहित मिलनी चाहिए थी किंतु इसके बावजूद लोगों को 7 से लेकर 10 हजार प्रति ट्राली के हिसाब से रेत मिल रही है। इस प्रकार रेत माफिया सरकारी दावों को हवा-हवाई करता नजर आ रहा है।

खदानों पर रात के समय धड़ल्ले से हो रही रेत चोरी

रेत खदानें शुरू न होने के कारण रेत माफिया रात के समय धड़ल्ले से सैकड़ों वाहन रेत के निकालकर खूब चांदी कूट रहा है, जिसके सबूत के तौर पर शहर में जगह-जगह पर लगे रेत के ढेर देखे जा सकते हैं और रेत माफिया मनमाने दाम वसूल रहा है।

अधिकारी - क्लीयरेंस मिलते ही मिलेगी रेत

जिला माइनिंग अधिकारी आलोक चौधरी ने बताया कि फाजिल्का जिले में चयनित की गई 19 रेत खदानों के लिए इनवायरमेंट क्लीयरेंस का काम पेडिंग है और क्लीयरेंस मिलते ही खदानों पर लोगों को सरकारी रेट पर रेत मिलनी शुरू हो जाएगी।

किसानों से जुड़े उद्यमों की क्षमता को बढ़ाकर खाद्य प्रणाली विकसित करने में सक्षम है भारत -अध्ययन

घाना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट 2023 में कहा गया है कि खाद्य संकट से निपटने वाले देश रोजगार, स्वास्थ्य और प्रकृति को बढ़ावा दे सकते हैं और कुल शून्य लक्ष्यों को भी बेहतर ढंग से हासिल कर सकते हैं।

इसमें भारत, घाना और वियतनाम को उन देशों में सूचीबद्ध किया गया है जो छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) की क्षमता को बढ़ाकर अपनी खाद्य प्रणाली विकसित करने में सक्षम हैं, विशेष रूप से वे उद्यम जो किसानों से जुड़े हुए हैं और स्थानीय खाद्य श्रृंखलाओं में काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब खाद्य प्रणालियां बदली जाती हैं, तो जलवायु परिवर्तन से लेकर स्थितिपरक आजीविका तक, दुनिया की कुछ सबसे कठिन समस्याओं को हल करने में मदद मिल सकती है।

परिवर्तनकारी खाद्य प्रणालियां किसानों और उत्पादकों के लिए स्वस्थ और पौष्टिक आहार और सम्मानजनक रोजगार प्रदान करती हैं। डब्ल्यूईएफ के सेंटर फॉर नेचर एंड क्लाइमेट के प्रबंध निदेशक जिम हुए नियो ने कहा कि यह रिपोर्ट बताती है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास जलवायु अनुकूलन और शमन प्रयासों में लोगों का समर्थन कैसे करता है।

बैन एंड कंपनी के सहयोग से तैयार की गई रिपोर्ट में अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और यूरोप के सात %प्रारंभिक प्रस्तावक% देशों से दोहराए जाने योग्य मॉडल प्रस्तुत किए गए, जिनका प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से काफी मजबूत रहा है और जिनके उदाहरण और सबक व्यापक रूप से प्रासंगिक हैं।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के मुख्य अर्थशास्त्री मैक्सिमो टोरेरो कुलेन ने कहा, देश के संदर्भ में, बेहतर खाद्य सुरक्षा और पोषण और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हमारी कृषि-खाद्य प्रणालियों को बदलने के लिए अलग-अलग रास्ते अपनाए जा सकते हैं। प्रकृति और स्वास्थ्य पर सीईओ एलायंस के सह-अध्यक्ष गेराल्डिन मैटचेट ने कहा जब भोजन विफल हो जाता है, तो सब कुछ विफल हो जाता है। भारत को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है, छोटे किसानों और डेयरी उद्यमों के दशकों के कार्यक्रम ने डेयरी को भारत की सबसे बड़ी कृषि वस्तु में बदलने में मदद की है, जो 2019 में ग्रामीण आय का लगभग एक-तिहाई और कुल कैलोरी सेवन का 10 प्रतिशत है। उन्होंने कहा यह बदलाव ग्रामीण स्तर की सहकारी समितियों, विस्तार सेवाओं और क्रेडिट के गठन का समर्थन करने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के साथ शुरू हुआ। समय के साथ यह एक ऐसे घरेलू उद्योग की खेती करने के लिए विकसित हुआ जिसमें किसान संबंधी सोर्सिंग मॉडल के साथ कई सफल, तकनीक, एकीकृत उद्यम हैं। डब्ल्यूईएफ ने कहा कि वियतनाम और घाना जैसे देशों ने इस बदलाव के रास्ते को अपनाया है। डेयरी भारत में एकमात्र सबसे बड़ी कृषि उद्यम है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत है और पोषण का एक महत्वपूर्ण आधार है। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है और इसके 70 प्रतिशत दूध का उत्पादन इसके 8 करोड़ छोटे किसानों द्वारा किया जाता है, जिनके पास 10 से कम पशु हैं। जैसा कि देश का शहरीकरण जारी है, शहर के निवासी डेयरी पर अधिक खर्च कर रहे हैं और अधिक प्रसंस्कृत डेयरी उत्पादों का उपभोग कर रहे हैं जो अधिक मुनाफे वाले हैं। 2002 से 2021 के बीच, क्षेत्र का मूल्यवर्धन दोगुना हो गया, 2020 में लगभग 15 बिलियन अमरीकी डालर दर्ज किया गया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादकः डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008